

मूकपत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 279 बेमेतरा, शुक्रवार 05 जून 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

आईएसआई और दाऊद नेटवर्क से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, मिंगस्टर नेटवर्क और दाऊद इब्राहिम से जुड़े माॅड्यूल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से आतंकी हुफैजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मुंबई में पिछले कई दिनों से स्पेशल सेल और एटीएस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की जा रही थी। इसी अभियान के दौरान हुफैजा को मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया। वह कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क और आईएसआई एजेंट मुन्ना झिंगाड़ा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, हुफैजा को कराची से निर्देश मिलते थे और वह उसी के अनुसार काम कर रहा था। वह मुंबई अंडरवर्ल्ड में सक्रिय नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। अब तक इस माॅड्यूल से जुड़े कुल नौ संदिग्धों को दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब सहित चार राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है।

अहमदाबाद में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

अहमदाबाद। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों से 290 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान 131 लोगों की पहचान अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है, जबकि करीब 160 अन्य संदिग्धों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने देर रात संयुक्त अभियान चलाकर चंडोला, गुलाबनगर और खोडियारनगर क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार, शहरभर में दस्तावेज सत्यापन और प्रवर्तन अभियान जारी है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पहचान, नागरिकता और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अगर हाथ-पैर काट दिए जाएं तो शायद लोग कानून का पालन करना सीख जाएं

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले को सुनवाई के दौरान अपराधों पर लुगाम लगाने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देते हुए सख्त दिष्णियां की हैं। अदालत ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण कानून का भय कम होता जा रहा है और यही वजह है कि गंभीर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। न्यायमूर्ति आर. नटराज ने 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराधों को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन और दोषियों को कड़ी सजा मिलना आवश्यक है। आरोपी छात्र अप्रैल की शुरुआत से न्यायिक हिरासत में हैं। और उस पर वर्ष 2023 में अपनी पूर्व सहपाठी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। जस्टिस आर. नटराज ने छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, कानून के दांत इसलिए टूट गए हैं, क्योंकि हम अपराधियों से सख्ती से नहीं निपटते। अगर आप किसी का हाथ या पैर काट दें।

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में लगी भीषण आग

दस से ज्यादा मरीजों की मौत की आशंका,बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली/ एजेंसी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बेहद दुखद और भयानक घटना सामने आई है। यहां के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई। यह आग सुबह करीब 3 बजे अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में लगी थी। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब इस हादसे ने सबको पूरी तरह से दहला दिया है। आग लगने के कारण पूरे अस्पताल परिसर में कुछ ही देर में अपरा-तफरी का माहौल बन गया था। जहरीला धुआं पूरे अस्पताल में तेजी से फैल गया जिससे मरीज काफी घबरा गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार अस्पताल में आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ियां तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर आईसीयू और अन्य वार्डों में फंसे मरीजों को बाहर निकाला। भारी मशक़त के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने 20 से ज्यादा मरीजों की सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बचाए गए सभी मरीजों को तुरंत शहर के अन्य सुरक्षित स्थानों और अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। अग्निशमन अधिकारी आर.एन. पांडेय के मुताबिक जब उनकी टीम पहुंची तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। राहत और बचाव कार्य के बावजूद इस भयानक हादसे में 10 से अधिक लोगों की जान चली गई। बचाए गए 20 मरीजों में से भी कई मरीजों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। पूरा आईसीयू वार्ड घने और काले धुएं से भर जाने के कारण कई मरीजों का दम घुट गया। एक पीड़ित परिजन ने रोते हुए बताया कि उनके पिता भी इसी आईसीयू में भर्ती थे जिनकी जान चली गई। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले बेगुनाह मरीजों के परिवारों में चीख-पुकार मच गई है। सभी लोग



सीएम ने जताया शोक,4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान

बिहार में मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग के कारण कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुःख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अधिकारियों ने अब तक चार मौतों की पुष्टि कर ली है। हालांकि, दस से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार लोगों की जान जाना अत्यंत दुःखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और इस कठिन समय में परिवारों को संबल दें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुआवजे का ऐलान करते हुए आगे लिखा, मृतकों के परिवारों को तत्काल 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पतालों में उचित व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार, प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर तुरंत पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर सफ़लापूर्वक काबू पा लिया है। राहत कार्यों की देखरेख के लिए झीएम एसपी नगर आयुक्त और सिविल सर्जन सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल के बाहर शोकान्कुल परिजन जमा हो गए, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कान्तेश मिश्रा ने बताया, अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



अस्पताल के बाहर अपने परिजनों की तलाश बचाकर वहां से तुरंत फरार हो गए। यहां तक कि प्रशासन ने मृत मरीजों के शव भी उनके परिजनों को नहीं सौंपे। अग्निशमन अधिकारी ने भी इस बात का पूरी तरह पुष्टि की है कि अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ वहां से गायब था। इस भयंकर लापरवाही के कारण अब अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

हरियाणा में बल्लभगढ़-जेवर एक्सप्रेसवे पर पलाईओवर से गिरी क्रेन, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी



हरियाणा के बल्लभगढ़-जेवर एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को भीषण हादसा हो गया है। पहरेरा खुर्द गांव के पास निर्माणाधीन पलाईओवर पर ये हादसा हुआ। पलाईओवर के ऊपर से एक क्रेन अचानक नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बचाव दल द्वारा दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इस इलाके में दोपहर के वक्त तेज बारिश हुई थी, जिससे निर्माण स्थल पर भारी कीचड़ और फिसलन हो गई। बारिश रुकने के कुछ देर बाद मजदूर दोबारा काम पर लग गए। गार्डर उठाने का काम चल रहा था। इसी दौरान कीचड़ की वजह से क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से पलट गई। वरमदीनों के अनुसार, हादसे के वक्त वहां पर कई मजदूर मौजूद थे। क्रेन के नीचे मजदूर दब गए। आसपास काम कर रहे अन्य मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस, निर्माण कंपनी के स्टाफऔर ग्रामीणों ने मिलकर मशीनों की मदद से क्रेन को हटाने और दबे लोगों को निकालने की कोशिश की। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अब तक 3 मजदूरों के मौत की पुष्टि हुई है। ये हादसा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का हिस्सा है। नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली-पनसीऔर के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे और पलाईओवर बनाए जा रहे हैं। ऋविबाद से जेवर तक का ये कॉरिडोर अपने वाले वक्त में हजारों वाहनों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता बनेगा।

दिल्ली अग्निकांड मामले

आरोपी लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस रिमांड..

नई दिल्ली/ एजेंसी



में पूरा सहयोग कर रहा है, इसलिए पुलिस रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उसके वकील ने यह भी मुद्दा उठाया कि उनको अभी तक सख्क की कॉपी नहीं दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के लिए। हालांकि, लवकेश बजाज की तरफसे इस रिमांड का विरोध किया और अदालत में कहा कि वो जांच

कॉपी उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस कई स्तरों पर जांच को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भी पत्र लिखकर इमारात का स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्वे कराने को कहा है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बिल्डिंग सुरक्षा मानकों पर खरी थी या नहीं। इसके साथ ही, बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस से भी भवन की बिजली कनेक्शन को लेकर जानकारी मांगी गई है और वर्तमान इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर जांच करने को कहा गया है। दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को भी पत्र लिखकर विस्तृत निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों-मदरसों में वंदे मातरम् पर बवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांगी छूट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम् के गायन को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों और मदरसों की प्राथना सभा में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एक ऐक ऐसी खबर सामने आ रही है, जो चुनावी राज्य में बीजेपी को परेशान कर सकती है। दरअसल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर से कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि अमरिंदर सिंह हमारे संपर्क में हैं। वह कांग्रेस के सीनियर नेता रह चुके हैं

एक साथ बीजेपी को दो बड़े झटके कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह

नई दिल्ली/ एजेंसी

पंजाब में अगले साल यानी की 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले राज्य में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एक ऐक ऐसी खबर सामने आ रही है, जो चुनावी राज्य में बीजेपी को परेशान कर सकती है। दरअसल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर से कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि अमरिंदर सिंह हमारे संपर्क में हैं। वह कांग्रेस के सीनियर नेता रह चुके हैं



और हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा के बीच दोस्ताना संबंध है। ऐसे में इस बात की चर्चाओं को इस लिए भी हवा मिला, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए वह लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन कई बार यह कह चुके हैं कि सिंह की कांग्रेस में वापसी कराने में सुझाव लिया जाता था, लेकिन बीजेपी सीधे दिल्ली से फैसले लेती है।

आई है। पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता प्रतिपाल सिंह बलियावाल ने कहा है कि संपर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है। रणदीप सुरजेवाला और कुमार शैलजा तो कहती हैं कि हुड्डा किसी के संपर्क में होने की बात की है। इसके कई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं को इस लिए भी हवा मिला, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए वह लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन कई बार यह कह चुके हैं कि सिंह की कांग्रेस में वापसी कराने में सुझाव लिया जाता था, लेकिन बीजेपी सीधे दिल्ली से फैसले लेती है।

भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना वेनेजुएला

भारत दौरे पर वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज दराबाद हाउस में पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता हुआ

नई दिल्ली। एजेंसी

द्विपक्षीय विकास पर चर्चा करने वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज दिल्ली पहुंचीं। गुरुवार को उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय मुलाकात की। इस अहम बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को अधिक मजबूत बनाना है। दोनों नेता ऊर्जा और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति रोड्रिगेज से मुलाकात की। उन्होंने भारत और वेनेजुएला

की साझेदारी को प्रगाढ़ करने की निरंतर प्रतिबद्धता की बहुत सराहना की। जयशंकर ने विश्वास जताया कि पीएम मोदी के साथ यह बैठक द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करेगी। यह ऐतिहासिक दौरा स्वास्थ्य और निवेश के क्षेत्र में कई नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है।भारत और वेनेजुएला के बीच हमेशा से ही ऊर्जा और वैश्विक दक्षिण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। रोड्रिगेज के साथ आया बड़ा प्रतिनिधिमंडल विभिन्न तकनीकी औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बहुत बारीकी से दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े विशेषज्ञ मुख्य रूप से शामिल हैं।



इनका मुख्य उद्देश्य भारत की तकनीकी क्षमताओं को समझना और निवेश के नए अवसर तलाशना है। भारत ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी पुराना विश्वसनीय साझेदार रहा है।

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वहां के ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही उल्लेखनीय निवेश किया है। ये कंपनियां वहां अपनी उपस्थिति को और भी अधिक बढ़ाने की नई संभावनाएं लगातार तलाश रही हैं।

इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को एक नई और स्थायी दिशा प्राप्त होगी। दवा उद्योग और स्वास्थ्य सेवा जैसे मानवीय क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं। परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि यह यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को बिल्कुल नई और तेज गति प्रदान करेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत और वेनेजुएला की कूटनीतिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत और सशक्त होगी। भारत लगातार अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है।

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बावजूद चुनाव बाद हिंसा और राजनीतिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीएमसी नेताओं पर हमलों, बढ़ते राजनीतिक तनाव और कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों ने राज्य की शासन व्यवस्था पर नई चिंता खड़ी कर दी है।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि यह बदलाव केवल सत्ता के स्तर पर हुआ है, जमीनी हकीकत

अब भी वही है। राज्य पहले की तरह ही चुनाव बाद की हिंसा और बदले की कार्रवाइयों में फंसा हुआ है। टीएमसी नेताओं पर हालिया हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पहले पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में निशाना बनाया गया। पार्टी इस मुद्दे को अदालत ले जाने और लोकसभा स्पीकर के सामने उठाने की तैयारी में है। इसके बाद, टीएमसी के चीफ विप कल्याण

बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली जिले में उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन पर हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस इन हमलों के लिए भाजपा पर आरोप लगा रही है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि ममता शासन के खिलाफ लोगों का दबा गुस्सा अब बाहर निकल रहा है।

हालांकि राजनीतिक हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। राज्य ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है और यह बदलाव राजनीतिक

बंगाल में चुनाव बाद फिर सुलगा सियासी संग्राम

परिदृश्य में भी दिखना चाहिए। भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाया था। अब सरकार में होने के नाते सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर आती है। किसी को भी किसी भी वजह से कानून हाथ में लेने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव बाद हिंसा बंगाल की बहुत पुरानी बीमारी है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी हिंसा के सैकड़ों केस दर्ज किए गए थे।

तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने

1900 से ज्यादा मामलों की जांच की थी। इसमें स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इससे न तो 2023 के पंचायत चुनाव और न ही 2024 के आम चुनावों में कोई सबक लिया गया। इस बार भी चुनाव परिणाम घोषित होते ही कई जगह से तोड़फोड़, मारपीट की खबरें आईं। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई। रिजल्ट आने के तीन दिन बाद ही बंगाल पुलिस ने 200 से ज्यादा केस दर्ज

कर 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अपने नेताओं पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने प्रदर्शन किया। उसके और सत्ताधारी भाजपा के बीच तनाव बना हुआ है। इसका असर शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे कार्यकर्ताओं तक दिख रहा है। कानून-व्यवस्था के लिहाज से यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार और विपक्ष के बीच अगर ऐसे ही टकराव चलता रहा, तो शासन से जुड़े कामकाज पर असर पड़ेगा।

‘शिंदे फॉर्मूला’ बंगाल तक पहुंचा! दीदी की टीएमसी में बिखराव के मिलने लगे संकेत

(सुधांशु माहेश्वरी)
टीएमसी में जारी बवाल में इस समय कुछ अहम पहलू दिखाई दे रहे हैं। नाराज विधायक, ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई और इस्तीफों का सिलसिला।पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार उसने सिर्फ सरकार नहीं बनाई, बल्कि बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी की टीएमसी को करारी शिकस्त दी। चुनाव में बीजेपी 208 सीटें जीतने में सफल रही जबकि टीएमसी का आंकड़ा 80 सीटों पर सिमट गया। बाद में दो विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में अब उनके पास विधानसभा में मात्र 78 सीटें हैं।

इस करारी शिकस्त के बाद मंथन करने के लिए टीएमसी ने तीन बार बैठक बुलाई। 6 मई को बैठक बुलाई गई तो 10 विधायक पहुंचे ही नहीं। फिर 19 मई को बैठक बुलाई गई तो 35 विधायक नदारद रहे। उसके बाद 31 मई को बुलाई गई बैठक में तो सबसे बड़ा खेल हुआ और 80 में से 60 विधायक मीटिंग में पहुंचे ही नहीं।

इसके ऊपर ममता की टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी भी लग चुकी है। टीएमसी प्रवक्ता बिस्वजीत देब ने इस्तीफा दिया है। शान्तनु सिंह, अभिजीत मजुमदार, काकोली घोष और अरुण चक्रवर्ती ने भी अपना पद छोड़ दिया है। इसके अलावा डायमंड हार्बर से 8 पार्षदों का इस्तीफा हुआ है। चंदननगर से 30 पार्षद, भाटपाड़ा से 30, गारुलिया से 18, हलिसाहर से 16, उत्तर बैरकपुर से 15 और कांचरापाड़ा से 14 पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं।

इन इस्तीफों के अलावा ममता बनर्जी ने उलूबेरिया से विधायक ऋद्रात बनर्जी और एंटली से विधायक संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया। आरोप लगा कि दोनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। लेकिन असल विवाद यह था कि इन दोनों ही विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष से जुड़े प्रस्ताव और उस पर लिए गए हस्ताक्षरों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। संदीपन साहा तो यहां तक कह चुके थे कि इसमें ऐसे विधायकों के हस्ताक्षर भी शामिल हैं जो असल में बैठक में शामिल तक नहीं हुए थे। इन आरोपों के बाद ही दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया गया।

विधायकों का नदारद होना, कुछको निष्कासित कर देना और लगातार इस्तीफों का सिलसिला इस बात की ओर जरूर इशारा करता है कि टीएमसी में इस समय सब कुछ ‘ऑल इज वेल’ नहीं है। मीडिया की एक रिपोर्ट दावा करती है कि कोलकाता के ‘विधायक हॉस्टल’ में टीएमसी नेताओं की एक सीक्रेट बैठक हो चुकी है। इस बैठक में निष्कासित विधायक के साथ-साथ कई असंगठित नेता शामिल हुए और टीएमसी के भविष्य, संगठनात्मक बदलाव और नए राजनीतिक विकल्पों को लेकर चर्चा की गई।

बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद पार्टी को कमजोर करने जैसी साजिशों के आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने की एक संगठित साजिश चलाई जा रही है। ममता का यह कहना ही बता

असल मेंमहाराष्ट्र में 2019 केविधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ। इस महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई और बीजेपी को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक और किरदार था। वह था एकनाथ शिंदे। बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने को राजी नहीं थे।



रहा है कि जमीन पर असंतोष है और उन्हें भी इस बात की चिंता जरूर सता रही है कि क्या टीएमसी टूट जाएगी।

टीएमसी में जारी बवाल में इस समय कुछ अहम पहलू दिखाई दे रहे हैं। नाराज विधायक, ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई और इस्तीफों का सिलसिला। जानकार इस पैटर्न की तुलना महाराष्ट्र से करने लगे हैं जहां 2022 में एकनाथ शिंदे ने भी एक बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने शिवसेना में दो फाड़ कर दी थी और कई विधायकों को अपने साथ लेकर पूरी पार्टी पर कब्जा जमा लिया था।

असल में महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ। इस महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई और बीजेपी को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस पूरे सियासी घटनाक्रम के एक और किरदार था। वह था एकनाथ शिंदे। बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने को राजी नहीं थे।

इसके बाद 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुए और पता चला कि एकनाथ शिंदे और कुछ दूसरे विधायक मुंबई से बाहर जा रहे हैं। फिर खबर आई कि वे गुजरात के सूरत पहुंच चुके हैं। आपले ही दिन कई विधायकों को लापता बताया गया। उद्धव ठाकरे ने खतरा देखते हुए आपात बैठक बुलाई, लेकिन कई विधायक पहुंचे ही नहीं। यहीं से संकेत मिल

चुके थे कि शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है।

इसके बाद 22 जून को शिंदे गुट असम के गुवाहाटी पहुंच गया। विधायकों की संख्या वहां बढ़ती गई। दावा किया गया कि 40 शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। फिर 22 से 28 जून तक दावों का खेल चलता रहा। शिंदे गुट की तरफ से लगातार कहा गया कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है और वह सरकार में नहीं बने रह सकते।

फिर 29 जून को फ्लोर टेस्ट की नौबत आई, लेकिन उसके ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। फिर 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। तब देवेन्द्र फडनवीस को डिटी सीएम बना दिया गया।

सरकार बना ली गई थी, लेकिन असली शिवसेना पर कब्जा करना बाकी था। ऐसे में यह मामला चुनाव आयोग के पास चला गया, जिसने 8 अक्टूबर 2022 को शिवसेना के धनुष-बाण वाले चुनाव चिन्ह को ही फ्रीज कर दिया। तब दो शिवसेना अस्तित्व में आई। एक का नाम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) रखा गया और दूसरी का नाम बालासाहेबांची शिवसेना यानी शिंदे गुट।

फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं असली शिवसेना को लेकर अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया और मामला चुनाव आयोग के पास ही रहा।

फिर 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना घोषित कर दिया। धनुष-बाण वाला चुनाव चिन्ह भी उनके खाते में गया। इस

तरह एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना पर अपना कब्जा कर लिया और उद्धव ठाकरे अलग-थलग पड़ गए। जानकार इसी को महाराष्ट्र का ‘शिंदे फॉर्मूला’ बताते हैं जहां सबसे पहले बागी विधायकों की नाराजगी को हवा दी जाती है, फिर उन्हें पक्ष बदलने के लिए मनाया जाता है और आखिर में सबसे बड़ा खेल होता है-दो फाड़। अब इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया के सामने आकर अभिषेक बनर्जी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ दबी जुबान ममता बनर्जी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। कई विधायकों का बैठकों से नदारद होना भी एक संकेत दे रहा है। इसी वजह से ऐसी अटकलें चल पड़ी हैं कि क्या 80 में से नदारद रहे 60 विधायक पार्टी को तोड़ भी सकते हैं?अभी इस सवाल का जवाब तो भविष्य की गर्भ में छिपा है, लेकिन ममता बनर्जी ने खतरे को भांपते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी है, लेकिन ममता ने भी तेवर दिखाते हुए दिल्ली कूच करने की चेतावनी दे दी है।यहां समझने वाली बात यह है कि सड़क पर उतरी ममता बनर्जी की असल पहचान भी यही है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी की एक स्ट्रीट फाइटर की इमेज है। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों ने उनकी छवि को मजबूत भी किया था। उन आंदोलनों के दम पर 34 साल के वामपंथी राज को भी खत्म किया गया था।

लेकिन तब की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा फर्क है। जब लेफ्ट से लड़ाई चल रही थी तब ममता की टीएमसी एकजुट थी। शुभेंदू अधिकारी जैसे बड़े नेता भी ममता के साथ खड़े थे। लेकिन आज की रणनीतियां और आज का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। बंगाल में बीजेपी की सरकार है, टीएमसी के कई विधायक ममता और अभिषेक से नाराज बताए जा रहे हैं, पार्टी के अंदर ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई छिड़ चुकी है और लगातार हो रहे इस्तीफे सियासी तात्मान बढ़ा रहे हैं।

ममता की सड़क पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर टीएमसी को खड़ा कर पाएगी? इस सवाल का जवाब ही टीएमसी का भविष्य भी तय करेगा और ममता दीदी की आगे की रणनीति भी। (यह

जहां हम खड़े होते हैं, हमारी रीढ़ भी वहीं खड़ी होती है

(अभिषेक पाण्डेय)
ऐन रैंड का उपन्यास द फाउंटेनहेड मौलिकता और भेड़चाल के संघर्ष को सामने लाता है। हावर्ड रॉक आत्मनिर्भर सोच और सिद्धांतों का प्रतीक है, जबकि पीटर कीटिंग सामाजिक स्वीकृति का। जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन ने सिर्फ भारी-भरकम डायलॉग भर नहीं बोला था बल्कि कॉन्फिडेंस से भरे इंसानी मिजाज, आत्मसम्मान और चरम व्यक्तिवाद की एक ऐसी हुंकार भरी, जो सदियों के सामाजिक बंधनों के एक झटके में तोड़ देती है। जब हम इस डायलॉग की गहराई में उतरते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह बात सीधे तौर पर उस वैचारिक धरातल से जुड़ती है, जिसे हमने कभी हावर्ड रॉक के मुंह से एकदम अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोलते हुए पढ़ा था - मैं किसी और के बोलीने पैदा करने वाली फैक्ट्रियां चला रहे हूँ, जहां युवा अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि समाज में रतबा दिखाने के लिए करियर चुनते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि समाज की नजरों में क्या कमी है, उसे सुधारो न कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारे अंदर की ताकत क्या है। यह जो कंडीशनिंग है, वह इंसान को अपनी शर्तों पर जीने के बजाय दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देती है। इस तरह हम फॉलोअर्स की जमात तो तैयार कर लेंगे लेकिन लीडर कहाँ से लाएंगे, यह कोई नहीं सोच रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई एल्गोरिदम के इशारों पर नाच रहा है और एकसी भेड़चाल का हिस्सा बनता है। रैंड के उपन्यास के हीरो हावर्ड रॉक को पसंद जरूर किया गया हो, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि हम सब धीरे-धीरे हावर्ड रॉक बनने का हौसला खो रहे हैं और पीटर कीटिंग की जमात में शामिल होते जा रहे हैं। अगर हम इस वैचारिक कशमकश को भारतीय संदर्भ में देखें, तो हमारी परवरिश की बुनियाद ही एक बिल्कुल अलग विरोधाभास पर टिकी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है ‘जैसा देश, वैसा भेष’। पहली नजर में यह बात सामाजिक सामंजस्य के लिए ठीक लगती है कि जहां रहो, वहां के सामाजिक माहौल में ढल जाओ लेकिन धीरे-धीरे यह मुद्दागरा हमारी मौलिकता यानी ओरिजिनेलिटी को मूलिकता का एक औज़ार बन जाता है और हमें पता नहीं चलता। सच तो यह है कि हमारी परवरिश कुछ इस तरह होती है कि हमें खुद को तलाशने के बजाय, समाज की कसौटियों पर फिट होने के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल जाओ, टीचर सवालों के जवाब लिखवा देती हैं और

उम्मीद करती हैं कि सभी बच्चे उसी

जवाब को रटा-रटया, जस का तस लिखें एग्जाम में। थोड़ा सा जवाब इधर-उधर हुआ नहीं, बच्चे ने वही बात अपनी भाषा में लिखी नहीं कि पूरे नंबर कट। स्कूल की कॉपियों से लेकर जीवन के फैसलों तक, हमारी तारीफ इस बात पर नहीं होती कि हमने नया क्या सोचा, बल्कि इस बात पर होती है कि हमने पहले से बनाए गए नियमों का कितनी खामोशी से पालन किया। यही भेड़चाल आगे चलकर हमारे करियर के फैसलों में दिखती है। बिना यह सोचे-समझे कि बच्चे का अपना टैलेंट क्या है, उसकी दिलचस्पी क्या है, लाखों बच्चों को कोटा, इंजीनियरिंग या पीएएससी की एक ही अंधी भट्ठी में झोंक दिया जाता है। किसी एक कोचिंग का रिजल्ट आया नहीं कि पूरा समाज अपने बच्चों को उसी रास्ते पर दौड़ा देता है। हम पीटर कीटिंग पैदा करने वाली फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जहां युवा अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि समाज में रतबा दिखाने के लिए करियर चुनते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि समाज की नजरों में क्या कमी है, उसे सुधारो न कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारे अंदर की ताकत क्या है। यह जो कंडीशनिंग है, वह इंसान को अपनी शर्तों पर जीने के बजाय दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देती है। इस तरह हम फॉलोअर्स की जमात तो तैयार कर लेंगे लेकिन लीडर कहाँ से लाएंगे, यह कोई नहीं सोच रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई एल्गोरिदम के इशारों पर नाच रहा है और एकसी भेड़चाल का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर इंस्टाग्राम पर कोई एक रील या ऑडियो विलप ट्रेंड कर गई, तो देश के लाखों लोग, चाहे वो स्टूडेंट हों, डॉक्टर हों या कोई और, अपनी गरिमा भूलकर उसी गाने पर एक जैसे स्टेप्स दोहराने लगते हैं। यह क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि डिजिटल गुलामी है। यहां तक कि हमारा घूमना-फिरना और सुकून भी अब फेयर आफ मिसिंग आउट और दूसरों को दिखाने की भेड़चाल से तय होता है। लोग किसी जगह को महसूस करने नहीं जाते, बल्कि सोशल मीडिया के बताए इंस्टा वारेथी या एस्पेटिक पॉइंट्स पर रील बनाने और फोटो खिंचने जाते हैं। पहाड़ों पर लगने वाला मौलों लंबा ट्रैफिक जाम प्रकृति प्रेम का नहीं, बल्कि इसी नकलची संस्कृति का नतीजा है।अगर आप भीड़ से अलग कोई राय रखते हैं या स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, तो डिजिटल दुनिया आपको तुरंत अलग-अलग कर देगी, कैसल या बॉयकॉट कर देने का डर दिखाने लगती है।

हिन्दी पत्रकारिता की दशा और दिशा

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पं. युगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रथम हिन्दी समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ के प्रकाशन के साथ हुई थी, जिसका अर्थ था ‘समाचार सूर्य’। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में कई समाचारपत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दी का पहला समाचारपत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया था। पहली बार उसकी केवल 500 प्रतियां ही छपी गई थी लेकिन चूंकि कलकत्ता में हिन्दी भाषियों की संख्या काफी कम थी और इसके पाठक कलकत्ता से बहुत दूर के भी होते थे, इसीलिए संसाधनों की कमी के कारण यह लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया। 4 दिसम्बर 1826 से ‘उदन्त मार्तण्ड’ का प्रकाशन बंद कर दिया गया लेकिन इस समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जा चुकी थी कि उसके बाद से हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं।

(योगेश कुमार गोयल)
अधिकांश हिन्दी समाचारपत्रों के अब ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश करके अनेक संफेदपोशों के चेहरों पर पड़े नकाब उतार फैकने का श्रेय भी पत्रकारिता जगत को ही जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं आंका जा सकता। भारत में प्रेस ने लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी महत्ता सिद्ध की है, फिर चाहे भारत-पाक युद्ध हो या भारत-चीन लड़ाई अथवा अन्य कोई चुनौतीपूर्ण अवसर। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि हिन्दी पत्रकारिता का स्थान इसमें सर्वोपरि रहा है। हिन्दी भाषी समाचारपत्र हों अथवा पत्रिकाएं, उनका देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ सदैव विशेष जुड़ाव रहा है और इस दृष्टि से राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं विकास की दिशा में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्षों के इतिहास में समय के साथ पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य बदलते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद सुखद स्थिति यह है कि हिन्दी पत्रकारिता के पाठकों या दर्शकों की रूचि में कोई कमी नहीं आई। यह अलग बात है कि अंग्रेजी मीडिया और उससे जुड़े कुछ पत्रकारों ने भले ही हिन्दी पत्रकारिता की उपेक्षा करते हुए सदैव उसकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिशें की हैं किन्तु वास्तविकता यही है कि पिछले कुछ दशकों में हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी ताकत का बखूबी अहसास कराया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। यह हिन्दी पत्रकारिता की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि कुछ हिन्दी अखबारों ने अनेक संस्करणों के साथ प्रसार संख्या के मामले में कुछ अंग्रेजी अखबारों को भी पीछे छोड़ दिया है।

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पं. युगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रथम हिन्दी

समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ के प्रकाशन के साथ हुई थी, जिसका अर्थ था ‘समाचार सूर्य’। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में कई समाचारपत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दी का पहला समाचारपत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया था। पहली बार उसकी केवल 500 प्रतियां ही छपी गई थी लेकिन चूंकि कलकत्ता में हिन्दी भाषियों की संख्या काफी कम थी और इसके पाठक कलकत्ता से बहुत दूर के भी होते थे, इसीलिए संसाधनों की कमी के कारण यह लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया।

4 दिसम्बर 1826 से ‘उदन्त मार्तण्ड’ का प्रकाशन बंद कर दिया गया लेकिन इस समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जा चुकी थी कि उसके बाद से हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं। ‘उदन्त मार्तण्ड’ के बाद अंग्रेजी शासनकाल में अनेक हिन्दी समाचारपत्र व पत्रिकाएं एक मिशन के रूप में निकलते गए किन्तु ब्रिटिश शासनकाल की ज्यादतियों के चलते उन्हें लंबे समय तक चलाते रहना बड़ा मुश्किल था, फिर भी कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने सराहनीय सफर तय किया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और हिन्दी पत्रकारिता भी मिशन न रहकर एक बड़ा व्यवसाय बन गई है किन्तु अच्छी बात यह है कि आज भी हिन्दी पाठक व दर्शक अपनी-अपनी पसंद के अखबारों व चैनलों के साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हैं।

बहरहाल, घर बैठे-बैठे दुनिया की सैर कराने की बात हो या देश-विदेश की हर छोटी-बड़ी हलचल से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों और हर प्रकार की नवीनतम जानकारियों को जुटाकर अपने पाठकों या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की, व्यवसायीकरण के आरोपों या तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिन्दी पत्रकारिता भी यह काम बखूबी कर रही है और आमजन के भरोसे पर खरा उतरते हुए हिन्दी पत्रकारिता आज आम जनजीवन का अभिन्न अंग बन

चुकी है। अधिकांश हिन्दी समाचारपत्रों के अब ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश करके अनेक संफेदपोशों के चेहरों पर पड़े नकाब उतार फैकने का श्रेय भी पत्रकारिता जगत को ही जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं आंका जा सकता।

जहां तक राष्ट्रीय अखंडता में प्रेस की भूमिका और इसके दायित्वों का प्रश्न है तो प्रेस के कई प्रमुख दायित्व माने गए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था की खामियों की प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथप्रष्टों को समर्पार्ण पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकड़ा बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पदों की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि शामिल हैं। प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, ‘प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं व विचारों को समझना और उन्हें सही ढंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है।’

लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अखण्डता के संदर्भ में पत्रकारिता की भूमिका की बात करें तो लोकतंत्र के अन्य स्तंभों के मुकाबले प्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्वभर में

भारत की प्रतिष्ठा के जो तीन प्रमुख कारण माने गए हैं, वे हैं जागरूक मतदाता, स्वतंत्र न्यायपालिका व स्वतंत्र प्रेस। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी ‘संसद’ की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए ही कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने का अथवा उसे जागृत करने के लिए जन संचार का सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

वर्तमान में जहां देशभर में नैतिक मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है और राजनीतिज्ञों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, वहीं हिन्दी पत्रकारिता भी इस नैतिक पतन का शिकार होने से नहीं बची है। फिर भी इतना संतोष तो किया ही जा सकता है कि इसने इसके बावजूद अधिकांश अवसरों पर सराहनीय भूमिका निभाई है। हालांकि आज के पूर्ण व्यावसायिकता के दौर में पत्रकारिता को अव्यवसायिक बनाए रखने की बात करना बेमानी होगा क्योंकि इस पेशे से जुड़े लोगों को भी अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना अनिवार्य होता गया है लेकिन व्यावसायिकता के इस दौर में भी इसे एक उद्योग-धंधे के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के चलते पत्रकारिता के मानदंडों को ताक पर रखने की प्रवृति से तो हर हल में बचना ही चाहिए।(लेखक 36 वर्षों से हिन्दी पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तक-भारत की रक्षा क्रांति’, ‘प्रदूषण मुक्त सांसें’ सहित कई चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं।)(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

नेत्राडाइन और एनएचईवी ने भारत के ई-हाईवे नेटवर्क पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई गति देने के लिए किया सहयोग

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित फ्लीट सुरक्षा एवं परिचालन तकनीक में वैश्विक अग्रणी कंपनी नेत्राडाइन (Netradyne) ने आज घोषणा की कि वह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम (NHEV) के उभरते इलेक्ट्रॉनिक हाईवे नेटवर्क के लिए इंटेलिजेंस और सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत एनएचईवी के एकीकृत ई- हाईवे इंफ्रस्ट्रक्चर में एक उन्नत डिजिटल इंटेलिजेंस लेयर जोड़ी जाएगी, जिससे लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुरक्षित, कनेक्टेड और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्राडाइन के एआई-संचालित समाधान चरणबद्ध तरीके से एनएचईवी समर्थित कॉरिडोर पर संचालित वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाए जाएंगे। इससे फ्लीट की रियल-टाइम निगरानी, संभावित जोखिमों की पूर्व पहचान, ड्राइवर व्यवहार का विश्लेषण और परिचालन मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह सहयोग पूर्व में किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स के अनुभवों पर आधारित है और एक तकनीक-सक्षम हाईवे इकोसिस्टम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनएचईवी देशभर में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे विकसित करने के राष्ट्रीय विजन पर कार्य कर रहा है, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर कनेक्टेड और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। वर्ष 2027 तक 26 प्रमुख हाईवे कॉरिडोर पर विस्तार की योजना बनाई गई है। चार्जिंग इंफ्रस्ट्रक्चर, ऊर्जा प्रबंधन, डिजिटल सिस्टम, वित्तीय सहयोग और परिचालन सहायता को एकीकृत करते हुए एनएचईवी भारत के लिए एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य लंबी दूरी के ईवी इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

मोटोरोला ने लॉन्च किया edge 70 pro+, जो 2026 का सबसे स्टाइलिश फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है

मोबाइल टेक्नोलॉजी व इनोवेशन में वैश्विक अग्रणी और भारत के प्रमुख 9 एआई स्मार्टफोन ब्रांड, मोटोरोला ने आज motorola edge 70 pro+ लॉन्च किया, जो 2026 का सबसे स्टाइलिश ऑल-राउंडर फोन है। बिना किसी समझौते के फ्लैगशिप अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया यह स्मार्टफ़ोन, प्रो-ग्रेड फ़ोटोग्राफी, प्रीमियम व विशिष्ट फ़िनिश, इमर्सिव एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट-जेन moto ai अनुभवों और फ्लैगशिप-लेवल परफ़ॉर्मेंस का एक शानदार संयोजन है। इस डिवाइस में क्राइ 50MP प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसका नेतृत्व कम रोशनी में बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए motoAI से लैस एडवांस सोनी LYTIA 710 कैमरा करता है। इसके साथ ही इसमें 50x एआई सुपर जूम प्रो के साथ 50MP का 3.5x पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो विज़न कैमरा और ऑटो फोकस ऑन-डिवाइस एआई क्षमताओं वाले मीडियाटेक डाइमेंशन 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर से पावर्ड, motorola edge 70 pro+ में पैंटोनर द्वारा चुने गए रंगों में शानदार सैटिन-लक्स, स्कल्पटेड वुड और टि्वल इंस्पायर्ड फ़िनिश के साथ ‘कलेक्शंस बाय मोटोरोला’ को पेश किया गया है। एक शानदार 144Hz 1.5K टर्न कलर क्राइ-कन्ट्रैस्ट पैंटोनर वैल्लिडेटेड डिस्प्ले, 90W टर्बोपावर™ चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ आने वाली विशाल 6500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, और IP68 + IP69 मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ मिलकर यह डिवाइस एक संपूर्ण फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन अनुभव प्रदान करता है।

किफायती फूड ऐप ‘टोइंग’ अब रायपुर में उपलब्ध

रायपुर: किफायती फूड डिलीवरी ऐप ‘टोइंग’ ने आज जालंधर में अपने लॉन्च की घोषणा की। पिछले 7+ महीनों में, टोइंग ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारत के 45 शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज की है और यह अपने ऐप पर खाने-पीने की सभी चीजों पर सबसे कम कीमत की गारंटी देता है, जो रेस्टोरेंट के टेबल मेन्यू की कीमत के बराबर या उससे कम होती है। इसके अलावा, टोइंग पर किए गए किसी भी ऑर्डर पर न तो पैसेजिंग चार्ज लिया जाता है और न ही कोई प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस। इससे टोइंग बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती फूड डिलीवरी ऐप बन जाता है। यूजर्स इस ऐप पर बिरयानी, बर्गर और बाउल जैसे कई तरह के व्यंजन 99 रुपये से कम में ऑर्डर कर सकते हैं। टोइंग, जिसे 2025 की दूसरी छमाही में पहली बार पुणे में लॉन्च किया गया था, अब आगरा, वडोदरा, गुवाहाटी, नासिक, नागपुर, पटना, औरंगाबाद, भोपाल, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम, नोएडा, फ़रीदाबाद, गाजियाबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, भुवनेश्वर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, लुधियाना, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम, सूरत, मंगलुरु, राजकोट, देहरादून, मुद्राई, तिरुपति, गोवा, जम्मू, कोटा, मैसूर, रांची, जालंधर और पटियाला में भी लाइव है।

भादूविप्रा ने सागर और रायगढ़ शहरों में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए मार्च 2026 के महीने के दौरान मध्य प्रदेश एलएसए के तहत सागर और रायगढ़ शहरों में किए गए इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट (IDT) के निष्कर्ष जारी किए हैं। ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और डेटा दोनों) की वास्तविक समय गुणवत्ता का आकलन और सत्यापन करना है। आईडीटी के दौरान, भादूविप्रा के द्वारा कवरेज, कॉल ड्रॉप रेट (CDR), कॉल सेटअप सक्सेज रेट (CSSR), डाटा डाउनलोड (छर) और अपलोड (UL) थ्रूपुट आदि जैसे प्रमुख सेवा गुणवत्ता (QOS) मानदंडों के लिए टीएसपी के निष्पादन को दर्ज किया जाता है और उन्हे उपभोक्ताओं की जानकारी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं(को अपनी सेवाओं में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

2. आई आईडीटी को शहरों, हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों आदि जैसे विविध उपयोग वाले वातावरण में सभी टीएसपी के स्थलीय मोबाइल नेटवर्क निष्पादन को कैचर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के ड्राइव टेस्ट में 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर सभी टीएसपी के सिम कार्ड का उपयोग करके लाइव डेटा और वॉयस सेशन स्थापित किए जाते हैं। कई उन्नत टेस्ट हैंडसेट का उपयोग किया जाता है और उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके रीयल टाइम में सेशन की निगरानी और विश्लेषण किया जाता है।

3. भादूविप्रा ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से मध्य प्रदेश एलएसए में 16 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 के दौरान सागर और रायगढ़ शहर में मिटी ड्राइव-455.1 किमी, हॉटस्पॉट स्टांनों-16, वॉक टेस्ट-9.7 किलोमीटर ड्राइव टेस्ट किए। ये टेस्ट भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की देखरेख में आयोजित किए गए थे।

पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय में समर कैंप का भव्य शुभारंभ, बच्चों में दिखा सीखने का उत्साह

मूक पत्रिका/बरमकेला। राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मक प्रतिभाओं के संवर्धन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश को सीखने और नवाचार का अवसर बनाने के उद्देश्य से पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस) सरसीवा में समर कैंप-2026 का शुभारंभ 03 जून को उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अतिथियों के बीच विशेष उत्साह देखने को मिला।

उद्घाटन समारोह में विद्यालय के प्राचार्य भरत लाल कुर्रे, प्रधान पाठक मीना जांगड़े, व्याख्याता उमेश कुमार जांगड़े, आर. के. भोई सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विद्यार्थियों को समर कैंप के महत्व से अवगत कराते हुए इसे अपने व्यक्तित्व और कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

प्राचार्य भरत लाल कुर्रे ने अपने उद्घाषधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल पुस्तक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में

सुशासन तिहार भाजपा कि नाकामी छुपाने का मंच,बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रही जनता, धरातल पर चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था– रेखचंद जैन.पूर्व विधायक

पंचायतों में 16वें वित्त की राशि का नहीं हुआ आज पर्यंत तक भुगतान,ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य प्रभावित,सरपंच जनपद सदस्य दे रहे स्तीफा

पंचायतों से हो रही सुशासन तिहार के लिए वसूली,राजस्व सहित हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर, भाजपा सरकार सिर्फआयोजनों व विज्ञापनों में पीट रही सुशासन का ढोल

मूक पत्रिका/जगदलपुर। जगदलपुर

आस्था से खिलवाड़ या विकास राशि की खुली लूट?

पांच लाख की लागत से बना गंगादेई माता मंदिर पांच साल में जर्जर, गुणवत्ताहीन निर्माण और टेका प्रथा पर उठे गंभीर सवाल

मूक पत्रिका/बकावंड। शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए लाखों रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और आस्था का सवाल का संरक्षण हो सके। लेकिन जब लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य कुछ ही वर्षों में बदहाल नजर आने लगें, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आखिर सरकारी राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया।

ऐसा ही मामला बकावंड जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मटनार से सामने आया है, जहां गंगादेई माता मंदिर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग पांच लाख रुपये की लागत से निर्मित मंदिर महज पांच वर्षों के भीतर ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। स्थिति यह है कि मंदिर परिसर में कहीं भी निर्माण कार्य की स्वीकृति संबंधी सूचना पट्ट या लागत विवरण बोर्ड तक नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।

गुणवत्ता पर सवाल, जिम्मेदारों पर उठी उंगली- ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर सहित पंचायत क्षेत्र में निर्मित कई सीसी सड़कें, पुलिया और अन्य निर्माण कार्य समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दीवारों में दरारें, उखड़ता प्लास्टर और कमजोर निर्माण सामग्री यह संकेत देती है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के



रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास का विकास भी आवश्यक है। पीएम श्री विद्यालयों में समर कैंप इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि के क्षेत्रों में नई-नई विधाएं सीख सकें और अपनी छिपी प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें निखार सकें।

समर कैंप के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, कला एवं शिल्प, टेराकोटा (मिट्टी कला), बांस शिल्प, ज्वेलरी मेकिंग, सेल्फी जोन निर्माण, मॉडलिंग एवं ब्यूटी पार्लर कोर्स, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, कम्प्यूनिकेशन स्किल विकास, टॉय मेकिंग, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, व्यक्तित्व विकास एवं अन्य कौशल

आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और जीवनोपयोगी कौशल भी प्राप्त होंगे।

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार समर कैंप का उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता का विकास करना, शारीरिक एवं मानसिक दक्षता बढ़ाना, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि विकसित करना, सामाजिक सहभागिता की भावना पैदा करना तथा नवाचार और

रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। साथ ही विद्यार्थियों को टीम वर्क, नेतृत्व और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों से भी परिचित कराया जाएगा।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सारंगदू के प्रसिद्ध गायक एवं मोर सारंगदू महान

विधानसभा के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने जारी प्रेस वृत्ति्सि के माध्यम से प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘सुशासन तिहार’ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत को छुपाने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार इस तरह के तड़क-भड़क वाले आयोजनों का सहारा ले रही है। आज धरातल पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आम जनता पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।

पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने सीधे तौर पर सरकार की वित्तीय नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाली पंचायतों को 16वें



वित्त आयोग की राशि आज पर्यंत तक जारी नहीं की गई है राशि के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बुनियादी

गीत से ख्याति प्राप्त रसायन विषय के व्याख्याता विद्या शंकर जायसवाल रहे। उन्होंने अपने गिटार की मधुर धुनों से कार्यक्रम में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर दिया। उनकी प्रस्तुति ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बच्चों को संगीत की विभिन्न विधाओं, गिटार वादन की तकनीकों तथा संगीत के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी। साथ ही संगीत के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और उसके सकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला।

विद्या शंकर जायसवाल ने बच्चों को बताया कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास, मानसिक एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन का भी महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और अनुशासन के साथ अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों ने भी गिटार की धुनों के साथ गीत गाए और संगीत की बारीकियों को सीखने में विशेष रुचि दिखाई। विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था।

समर कैंप के पहले दिन विद्यालय का वातावरण पूरी तरह उत्सवमय नजर आया। कहीं बच्चे चित्रकारी कर रहे थे, तो कहीं संगीत और कला की गतिविधियों

में भाग ले रहे थे। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपने-अपने रुचि क्षेत्रों के अनुसार गतिविधियों का चयन कर उनमें सहभागिता दिखाई। शिक्षकों द्वारा भी बच्चों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे वे गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि आगामी दिनों में भी समर कैंप के अंतर्गत अनेक रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय कलाकारों, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा और उनके अंदर आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

समर कैंप के प्रथम दिवस पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह, उमंग, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा की अद्भुत झलक देखने को मिली। बच्चों के चेहरे नई चीजें सीखने की खुशी से खिल उठे थे। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अतिथियों की सक्रिय सहभागिता से कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत सफल और प्रेरणादायक रहा। विद्यालय परिवार ने विश्वास व्यक्त किया कि यह समर कैंप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व निर्माण और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

समर कैंप का उद्देश्य

का म न करा पाने के कारण जनता के प्रति जवाबदेह सरपंच और जनपद सदस्य भारी मानसिक दबाव में हैं और लगातार अपने पदों से इस्तीफे दे रहे हैं।

पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है,वहीं दूसरी तरफतथाकथित‘सुशासन तिहार’ के भव्य आयोजनों का खर्च निकालने के लिए पंचायतों से जबरन वसूली की जा रही है।यह सुशासन नहीं बल्कि शासकीय तंत्र का घोर दुरुपयोग और भाजपा के कुशासन का जीता-जागता उदाहरण है

सरकार को घेरते हुए पूर्व विधायक ने आगे कहा कि आज राजस्व विभाग से लेकर हर छोटे-बड़े

सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना लेन-देन के आम जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। नामांतरण,बंटवारा और सीमांकन जैसे नियमित कार्यों के लिए भी गरीब ग्रामीणों को महीनों चक्कर काटने पड़ रहे हैं।भाजपा सरकार केवल विज्ञापनों और आयोजनों में सुशासन का ढोल पीट रही है,जबकि हकीकत यह है कि जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त है और अधिकारी-कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार को सख्त चेतावनी देती कि यदि जल्द ही 16वें वित्त की राशि जारी नहीं की गई और पंचायतों में विकास कार्य बहाल नहीं हुए,तो आगामी दिनों में जनता के हक के लिए सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी।



क्या संबंधित अधिकारियों ने समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया था? क्या उपयंत्री और तकनीकी अधिकारियों ने गुणवत्ता की जांच की थी? यदि जांच हुई थी, तो फिर आज निर्माण कार्यों की स्थिति ऐसी क्यों है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ग्रामीण जानना चाहते हैं।

आस्था के केंद्रों से जुड़ा जनविश्वास- गंगादेई माता मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे धार्मिक स्थलों के निर्माण में यदि अनियमितता या गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायतें सामने आती हैं, तो यह केवल सरकारी धन की बर्बादी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ जाता है।

ग्रामीणों का मानना है कि आस्था के केंद्रों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

उच्च स्तरीय जांच की मांग- मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी की देखी जा रही है। उनका कहना है कि पंचायत क्षेत्र में हुए ऐसे सभी निर्माण

कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भुगतान प्रक्रिया और तकनीकी स्वीकृतियों की भी जांच कर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है।

यह मामला केवल एक मंदिर या एक निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यदि जनता के टैक्स के पैसे से बने निर्माण कार्य कुछ ही वर्षों में बदहाल हो जाएं, तो इसकी निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाना लोकतंत्र और जवाबदेह शासन व्यवस्था की मूल आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ यह विषय जनचर्चा और जनजागरूकता के लिए सामने लाया गया है, ताकि भविष्य में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

